

सच्चा वादा-पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मिनी ओलंपिक मापदंड पर आधारित स्विमिंग पूल का किया शुभारंभ

शहडोल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सच्चा वादा-पक्का काम ही राज्य सरकार की पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय भाई-बहनों के सर्वांगीण विकास में जुटी है। जनजातीय भाई-बहनों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शहडोल जिले के धनपुरी में नगर पालिका द्वारा 20 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए वॉटर पार्क के लोकार्पण अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रविवार को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का साफा तथा गजमाला पहनाकर अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गीता भवन निर्माण की घोषणा करते हुए कहा कि इसके बन जाने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाइब्रेरी और कोचिंग जैसी शैक्षणिक गतिविधियों के



संचालन में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहडोल सिंचाई काम्प्लेक्स निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत सोन नदी पर 4 माइक्रो सिंचाई

परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। लगभग 2300 करोड़ रुपए की इस योजना से 50 हजार हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, जिससे 122 गांव को लाभ होगा। मुख्यमंत्री डॉ.

यादव ने जैतपुर को नगर पंचायत बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के संबंध में विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर सीट वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शहडोल जिले में 160 करोड़ रुपए लागत से 45 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा जैतपुर महाविद्यालय में कला और विज्ञान संकाय के भवन निर्माण की घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवीन महाविद्यालय आरंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने 3 किलोमीटर लंबे मॉडल रोड निर्माण पर भी सहमति प्रदान की।

मुख्यमंत्री की घोषणाएं

- शहडोल सिंचाई काम्प्लेक्स की घोषणा
- जैतपुर बनेगी नगर पंचायत
- शहडोल में बनेगा गीता भवन
- मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें
- नए महाविद्यालय की दो सौगात
- 3 किलोमीटर लंबा मॉडल रोड बनेगा

माता-बहनों के लिए सरकार समर्पित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता बहनों के कल्याण के लिए पूरी सरकार समर्पित है इसीलिए लाइली बहना योजना सहित महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना, लखपति ड्रोन दीदी योजना, रजिस्ट्री में माता-बहनों को 2 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। लोकसभा-विधानसभा में भी बहनों को आरक्षण मिलने वाला है। आने वाला समय माता-बहनों का है, हमारी संस्कृति बहनों के आधार पर ही पुष्पित पल्लवित होती रही है।

महिलाओं का कल्याण सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने कहा- भारत वैश्विक मंच पर प्रमुख आर्थिक शक्ति बन कर उभर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अमेरिका से हुए समझौते में किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। केंद्र हो या राज्य सरकार युवा, गरीब, किसान और महिलाओं का कल्याण सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश कृषि हो या उद्योग सभी क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 44 लाख हेक्टेयर हुआ है। युवाओं को भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

देश-प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है

सांसद हिमाद्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में देश-प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। इसी का परिणाम है कि धनपुरी को मिनी ओलंपिक के मापदंड पर आधारित स्विमिंग पूल की सौगात मिली है। नगर पालिका धनपुरी की अध्यक्ष रविंदर कौर छबड़ा ने स्वागत भाषण दिया तथा नगर पालिका द्वारा निर्मित वॉटर पार्क और अन्य संचालित गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर नगरीय निकाय तथा पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीयजन उपस्थित थे।

‘आवेश में निकले थे शब्द’

मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया मामले में चौथी बार माफी मांगी



भोपाल

कर्नल सोफिया को लेकर दिए बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से दो दिन पहले प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। शाह ने कहा- मैंने पहले भी कई बार कहा है, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज, किसी वर्ग का अपमान हो। वे शब्द निस्संदेह मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। वे शब्द देश भक्ति के उत्साह, उत्तेजा और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं कि मेरी कोई दुर्भावना नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा

जिम्मेदारी मानता हूं। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः उस मामले में आप सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से, सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मामले में मध्यप्रदेश सरकार को 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। सरकारी और राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और समय मांग सकती है। तर्क यह दिया जाएगा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और विस्तृत परीक्षण जरूरी है। यही रुख शुरुआत से मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम का भी रहा है।

प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति मनोबल टूटने पर ही अपशब्द बोलेगा : खड़गे

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष



मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति यदि अपशब्द और असत्य बोलने लगता है तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि उनमें कोई हताशा है जिसके कारण उनका मनोबल टूट गया है। श्री खड़गे ने प्रधानमंत्री के राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिये गये जवाब पर एक वीडियो पोस्ट में शक्रवार को कहा कि श्री मोदी ने 97 मिनट पर अपना भाषण दिया और इसमें वह सब असत्य ही दोहराते रहे हैं। जब हमने अभिभाषण पर अपनी बातें रखी उनका भी प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ 100 साल.. 75 साल.. 50 साल की बात करते रहे। इसका मतलब यही है कि श्री मोदी के पास हमारे पूछे गए सवालों का जवाब देने की शक्ति ही नहीं है।

बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगमियां तेज हो गई हैं। इस बीच राज्य कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि पार्टी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस आलाकमान से विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है। बंगाल कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, सांसद ईशा खान चौधरी समेत राज्य के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विस्तृत चर्चा हुई।

सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती, नक्सली हथियार डाल दें: शाह

रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विगत दिवस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर उच्चस्वतरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राज्य में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा-केंद्रित रणनीति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनैशियल नेटवर्क पर कड़ा प्रहार और प्रभावी आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती, नक्सली हथियार

डाल दें, रेड कार्पेट बिछकर स्वागत करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि कभी नक्सली हिंसा का गढ़ रहा छत्तीसगढ़, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के चलते विकास का पर्याय बन चुका है। गृह मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ के युवा अब खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद ने देश की कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेला, लेकिन अब देश इस अभिशाप से मुक्ति के बेहद करीब है। मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि माओवाद के खिलाफ लड़ाई बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए और केन्द्र व राज्यों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।



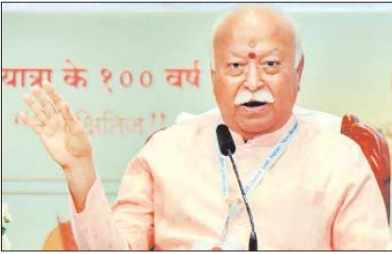
कोई भी हिंदू बन सकता है आरएसएस प्रमुख

कहा- संघ कहे तो पद छोड़

दूंगा : मोहन भागवत

मुंबई।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि यदि संघ उनसे पद छोड़ने को कहेगा, तो वे तुरंत ऐसा करेंगे। आमतौर पर 75 साल की उम्र के बाद किसी पद पर नहीं रहने की परंपरा की बात कही जाती है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सरसंघचालक बनने के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र या ब्राह्मण होना कोई योग्यता नहीं है। जो हिंदू संगठन के लिए काम करता है। वही सरसंघचालक बनता है। भागवत रविवार को मुंबई में आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीर सावरकर को भारत रत्न दिया गया तो इससे



पुरस्कार की गरिमा और बढ़ेगी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि समान नागरिक संहिता सभी को विश्वास में लेकर बनाई जानी चाहिए और इससे समाज में मतभेद नहीं बढ़ने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीद है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारत के हितों को ध्यान में रखकर किया गया होगा और देश को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। घुसपैठ के मुद्दे पर आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सरकार

को बहुत काम करना है। पहचान कर निष्कासन की प्रक्रिया होनी चाहिए। यह पहले नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब धीरे-धीरे शुरू हुआ है और आगे बढ़ेगा। आरएसएस का काम प्रचार करना

नहीं, बल्कि समाज में संस्कार विकसित करना है। जरूरत से ज्यादा प्रचार से दिखावा और फिर अहंकार आता है। प्रचार बारिश की तरह होना चाहिए। सही समय पर और सीमित मात्रा में।

अंग्रेजी कभी मुख्य भाषा नहीं बनेगी

आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ अपने स्वयंसेवकों से आखिरी बूंद तक काम लेता है। आरएसएस के इतिहास में अब तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई, जब किसी को जबरन रिटायर करना पड़ा हो। भागवत ने कहा कि संघ की कार्यप्रणाली में अंग्रेजी कभी मुख्य भाषा नहीं बनेगी, क्योंकि यह भारतीय भाषा नहीं है। जहां जरूरत होती है, वहां अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन मातृभाषा को नहीं भूलना चाहिए।

संघ नहीं चलाता सरकार

संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ किया कि संघ सरकार नहीं चलाता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी अलग हैं। प्रोपेगेंडा खस, स्वयंसेवक कहीं भी हों पर संगठन का राजनीति से सीधा वास्ता नहीं है। संघ ने पहले से तय किया हुआ कि समाज के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं करना है। संघ के पास केवल एक ही काम है वह समाज को एक करना है। मोहन भागवत ने कहा कि परिस्थितियों का विचार करने से फायदा नहीं है, बल्कि हमें उन परिस्थितियों में कैसे काम करना है, इसका विचार करना चाहिए।



तमिल भाषा ने भारत और मलेशिया के दिल को जोड़ा-प्रधानमंत्री मोदी

कुआलालंपुर।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया तमिल भाषा के प्रति साझा स्नेह से जुड़े हुए हैं। मोदी ने देश में शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में इस भाषा की मजबूत उपस्थिति को रेखांकित किया। मलेशिया में भारतीय मूल के लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या समूह है। इनमें से अधिकांश तमिल मूल के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, भारत और मलेशिया तमिल भाषा के प्रति साझा स्नेह से भी जुड़े हुए हैं। मलेशिया में शिक्षा, मीडिया और सांस्कृतिक जीवन में तमिल की मजबूत व जीवंत उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आज का यह ऑडियो-विजुअल समझौता फिल्मों और संगीत, विशेषकर तमिल सिनेमा के माध्यम से हमारे दिलों को और भी करीब लाएगा। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम भारत में हममें से कई लोगों की तरह, एमजीआर (अभिनेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचन्द्रन) के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में आयोजित दोपहर के भोजन के दौरान तमिल अभिनेता की फिल्म नालाई नमाधे का एक गीत प्रस्तुत किया गया। एमजी रामचन्द्रन, एक लोकप्रिय भारतीय अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे। उन्होंने तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कण्णम (अन्नाद्रमुक) पार्टी की स्थापना की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। रामचन्द्रन का निधन 1987 में हुआ था।

सरकार के मसले हैं वोटर लिस्ट-नागरिकता

सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया अपना जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के केस में अपना जवाब दाखिल किया है। विगत दिवस राउज एवेन्यू कोर्ट को दिए जवाब में कहा उनके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका गलत और अनुमार्गित तथ्यों पर आधारित है। यह याचिका ओछी राजनीति से प्रेरित और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। स्पेशल जज विशाल गोगने को कोर्ट में वकील के जरिए दायर जवाब में सोनिया ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में शामिल होने से जुड़े आरोपों का खंडन किया। साथ ही पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग की है। मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। सोनिया गांधी ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता ने ऑर्थेंटिक रिकॉर्ड की जगह अनुमानों, मीडिया रिपोर्टों और व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर लापरवाही से गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में किसी भी खास दस्तावेज को जाली या गलत साबित नहीं किया गया है और जरूरी विवरण की कमी है। उन्होंने



कहा कि नागरिकता से जुड़े मामले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि वोटर लिस्ट तैयार करना और उसका रखरखाव चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे मामलों में आपराधिक अदालतें अगर किसी व्यक्ति की निजी शिकायत पर दखल देती हैं, तो यह सही नहीं है। क्योंकि ऐसा करना चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा। गौरतलब है कि 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव वकील के जरिए दायर जवाब में सोनिया ने भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले वोटर लिस्ट में शामिल होने से जुड़े आरोपों का खंडन किया। साथ ही पुनर्विचार याचिका को खारिज करने की मांग की है। मामले की सुनवाई अब 21 फरवरी को होगी। सोनिया गांधी ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि शिकायतकर्ता ने ऑर्थेंटिक रिकॉर्ड की जगह अनुमानों, मीडिया रिपोर्टों और व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर लापरवाही से गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों में किसी भी खास दस्तावेज को जाली या गलत साबित नहीं किया गया है और जरूरी विवरण की कमी है। उन्होंने

चौरसिया ने विकास त्रिपाठी की शिकायत को खारिज कर दिया था। त्रिपाठी ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिट्यू पिटीशन दायर की। 9 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया था। त्रिपाठी का कहना है कि गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में ही भारत की नागरिक नहीं थीं। त्रिपाठी ने यह भी दावा किया कि 1982 में सोनिया का नाम हटा दिया गया था और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया था।

संजय शूज

SANJAY SHOES

Ganjipura Chowk, Jabalpur
91318 41474



संपादकीय

डील के कई विरोधाभास

अमरीका से कृषि उत्पाद भारत में आएंगे और गेहूँ, ज्वार, जौ, बाजरा, ओट्स, चावल, मक्का आदि बाजार में नहीं आएंगे। डेयरी क्षेत्र में भी अमरीका भारत के बाजार में प्रवेश करेगा, लेकिन हमारे किसान, उधमी और एमएसएमई सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। ऐसा आशासन प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिया है। व्यापार समझौते का जो मसविदा, ढांचा सामने आया है, बेशक वह अंतरिम है, लेकिन कई विरोधाभासों वाला है। गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, पॉल्ट्री, मीट, केला, स्ट्रबेरी, चेरी, हरा मटर, मूंग, काबुली चना, तेल के बीज, तंबाकू, इथनॉल और डेयरी उत्पादों पर अमरीका हमें कोई छूट और रियायत नहीं देगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दावा कर रहे हैं कि दूध, क्रीम, छाछ, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर आदि डेयरी उत्पाद अमरीका से भारत में नहीं आएंगे। मसाले भी नहीं आएंगे, लेकिन समझौते के मसविदे, ढांचे में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि दूध, जीएस गेहूँ एवं मक्का, सोयाबीन आदि उत्पाद अमरीका भारत में नहीं भेजेगा। समझौते में कई गंभीर विरोधाभास हैं। अर्थात अमरीका हमारे कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भी अपना कारोबार करेगा। क्या भारतीय किसान अमरीकी किसानों की प्रतिस्पर्द्धा में टिक सकेंगे? अमरीकी किसानों की लागत भारतीय किसानों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि उन्हें अरबों की सबसिडी दी जाती है, जबकि भारतीय सबसिडी ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ समान है। क्या एसबीआई की रपट बिल्कुल सही, सटीक साबित होगी और भारतीय किसानों, पशुपालकों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ सकता है? बहरहाल मार्च मध्य में जब समझौते का अंतिम मसविदा सार्वजनिक होगा और जिस पर दोनों देशों के प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेंगे, तब तक कुछ और संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर व्यापार समझौते की शर्तें तय हो चुकी हैं। लिहाजा सबसे संवेदनशील सवाल यह है कि क्या अमरीका को उन क्षेत्रों में घुसने की अनुमति दे दी गई है, जिन पर भारत सरकार साफ इंकार करती रही है? एक बार अमरीकी उत्पादों का भारत में सैलाब आएगा, तो फिर वह रुकने वाला नहीं है?

क्या भारत सरकार अमरीकी कृषि और डेयरी उत्पादों पर इतना टैरिफ लगा सकती है कि वे भारतीय बाजार में, हमारे किसानों के साथ, प्रतिस्पर्द्धा करने में पिछड़ जाएं? समझौते के मसविदे में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। बहरहाल अभी तो हमें प्रधानमंत्री मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयानों और दावों पर भरोसा करना चाहिए। रूस के कच्चे तेल से जुड़ी अमरीका की चेतावनी भी बेहद गंभीर है। सवाल है कि भारत किस देश से, कितना तेल-गैस आदि, खरीदता है, इस संप्रभु निर्णय में अमरीका का दखल क्यों होना चाहिए? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा प्रशासनिक आदेश भी जारी कर दिया है कि यदि भारत, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, रूस से तेल खरीदता पाया जाता है, तो उस पर 25 फीसदी पेनल्टी टैरिफ एक बार फिर लगाया जा सकता है। इस बिंदु पर भारतीय वार्ताकार एहमत क्यों हुए? रूस भारत का पुराना और आजमाया हुआ मित्र-देश है। भारत ने जनवरी, 2026 में भी रूस से 251 टन तेल प्रतिदिन खरीदा है। बेशक भारत ने रूसी तेल की खरीद कम की है, लेकिन यह भी गौरतलब तथ्य है कि रूसी तेल खरीदने से भारत को बीते 40 माह में 1.53 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है। तेल का यह कारोबार ‘रुपए-रुबेल’ में हुआ है। अप्रैल-मई तक का रूसी तेल का हमारा ऑर्डर पहले ही दिया जा चुका है।

परीक्षा के एक-दो दिन पहले कैसे करें प्रभावी तैयारी

परीक्षा के ठीक पहले के एक-दो दिन किसी भी विद्यार्थी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यही वे दिन होते हैं, जब को गई तैयारी परीक्षा के परिणाम को दिशा देती है। कई छात्र इस समय अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं, तो कुछ लापरवाही बरत लेते हैं। दोनों ही स्थितियाँ नुकसानदायक होती हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि परीक्षा के एक-दो दिन पहले किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, जिससे आत्मविश्वास बना रहे, याद की हुई बातें सुरक्षित रहें और परीक्षा के दिन सर्वोत्तम प्रदर्शन किया जा सके।

सबसे पहले मानसिक स्थिति को संतुलित करें

परीक्षा से ठीक पहले मन का शांत होना सबसे आवश्यक है। घबराहट, डर और अनावश्यक चिंता याद की हुई जानकारी को भी भ्रमित कर देती है। इस समय यह स्वीकार करना चाहिए कि आपने जितनी तैयारी की है, वही अब आपकी पूँजी है।

अपने आप से बार-बार यह न कहें कि ‘मुझे कुछ नहीं आता।’ सकारात्मक वाक्य दोहराएँ – ‘मैंने मेहनत की है, मैं अच्छा करूँगा।’ गहरी साँस लें, 5–10 मिनट ध्यान (मेडिटेशन) या प्राणायाम करें। नकारात्मक सोच वाले लोगों या डर फैलाने वाली चर्चाओं से दूरी रखें। मानसिक शांति अच्छी तैयारी की पहली शर्त है।

नया पढ़ने की गलती न करें

परीक्षा के एक-दो दिन पहले नया पाठ या नया अध्याय शुरू करना सबसे बड़ी भूल होती है। इससे पहले से पढ़ी हुई चीजों में भी प्रश्न पैदा हो जाते हैं। केवल वही विषय दोहराएँ जो पहले पढ़ चुके हैं। कठिन टॉपिक

खबर प्लेटफार्म

(हिन्दी साप्ताहिक)

ऑनलाइन गेम्स की लत और बच्चों की मौतें : डिजिटल युग का भयावह सच

दीपक पच्चौरी ‘दीप’

डिजिटल क्रांति ने भारत सहित पूरी दुनिया के जीवन को अभूतपूर्व रूप से बदल दिया है। इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं। भारत में वर्ष 2024 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 85 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिनमें एक बड़ा हिस्सा बच्चों और किशोरों का है। लेकिन इसी डिजिटल सुविधा के साथ एक गंभीर और भयावह संकट भी जन्म ले रहा है—ऑनलाइन गेम्स की लत, जो अब बच्चों की मानसिक सेहत ही नहीं, बल्कि उनकी जान तक लेने लगी है।

आंकड़े जो चिंता बढ़ाते हैं

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में बच्चों और किशोरों में आत्महत्या के मामलों में पिछले पाँच वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि आत्महत्या के पीछे कारण बहुस्तरीय होते हैं, लेकिन विभिन्न राज्य पुलिस रिपोर्ट और मीडिया जांचों में यह सामने आया है कि— कई मामलों में ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध, गेम में हार, या मोबाइल छीन लिए जाने के बाद बच्चों ने आत्मघाती कदम उठाए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में स्क्रीन एडिक्शन एक गंभीर मानसिक विकार के रूप में उभर रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 30 प्रतिशत बच्चे रोजाना 3 से 5 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। 10 प्रतिशत से अधिक बच्चे 6 घंटे से ज्यादा समय मोबाइल या गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। ये आंकड़े केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरों की घंटी हैं।

वास्तविक घटनाएँ—जब खेल बना मौत का कारण

पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं, जिन्होंने पूरे समाज को झकझोर दिया। तमिलनाडु में एक 14 वर्षीय छात्र ने ऑनलाइन गेम खेलने से रोके जाने पर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र में एक किशोर ने गेम में पैसे हारने के बाद



फांसी लगा ली। तेलंगाना और कर्नाटक में कई मामलों में बच्चे रात-रात भर गेम खेलते रहे, पढ़ाई और सामाजिक जीवन से कट गए और अवसाद में चले गए। इन घटनाओं में एक समानता स्पष्ट है बच्चों की मानसिक स्थिति को समय रहते समझ नहीं गया।

ऑनलाइन गेम्स-मनोरंजन नहीं, मनोवैज्ञानिक जाल—आज के ऑनलाइन गेम केवल खेल नहीं हैं। इन्हें विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों की मदद से इस तरह डिजाइन किया जाता है कि खिलाड़ी अधिक से अधिक समय तक जुड़े रहें। इनमें शामिल होते हैं—रिवॉइ और पनिशमेंट सिस्टम, लेवल अप करने का लालच, वरचुंअल पहचान और प्रतिष्ठा, लगातार नोटिफिकेशन और दबाव। जब बच्चा जीतता है, तो उसे नकली आत्मसंतोष मिलता है, और जब हारता है, तो वह खुद को असफल मानने लगता है। धीरे-धीरे बच्चा वास्तविक दुनिया की समस्याओं से भागकर वरचुंअल दुनिया में शरण लेने लगता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर

मनोचिकित्सकों के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग की

लत से बच्चों में अवसाद, चिंता, चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, आक्रामक व्यवहार तेजी से बढ़ रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी गेमिंग डिस्ऑर्डर को एक मानसिक विकार के रूप में मान्यता दी है। यह स्पष्ट संकेत है कि यह समस्या अब केवल सामाजिक नहीं, बल्कि चिकित्सकीय संकट भी बन चुकी है।

परिवारों पर टूटता कहर

जब कोई बच्चा इस तरह अपनी जान देता है, तो केवल एक जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार मानसिक रूप से टूट जाता है। माता-पिता— जीवन भर अपराधबोध में जीते हैं। समाज की चुप्पी और सवालों से जूझते हैं। खुद को असफल मानने लगते हैं। एक मध्यमवर्गीय परिवार, जो अपने सीमित संसाधनों में बच्चे को बेहतर भविष्य देना चाहता है, जब इस त्रासदी से गुजरता है, तो उसका दर्द शब्दों से परे होता है।

माता-पिता और समाज की चुनौती

अक्सर माता-पिता बच्चों को मोबाइल देकर यह मान लेते हैं कि बच्चा सुरक्षित है। लेकिन यह डिजिटल

संबंधों में तनाव से दरकते रिश्ते

पिछले कुछ वर्षों में समाज का एक स्पष्ट और चिंताजनक संकेत सामने आया है कि युवा वर्ग विवाह जैसे पारंपरिक बंधन से दूरी बना रहा है और जहाँ विवाह हो भी रहा है, वहीं संबंधों में जल्द ही तनाव, असंतोष और अंततः तलाक की स्थिति पैदा हो जा रही है। यह स्थिति केवल लड़कों तक सीमित नहीं है। लड़कियाँ भी समान रूप से विवाह और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर असमंजस में हैं। माता-पिता की इच्छा, अनुभव और समझ अब पहले जैसी निर्णायक नहीं रह गई है। इस बदलाव को केवल ‘पश्चिमी प्रभाव’ या ‘नैतिक गिरावट’ कहकर टाल देना ईमानदार विश्लेषण नहीं होगा। इसके पीछे गहरे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारण हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है।

आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, आत्मनिर्भर और समझ अव पहले जैसी निर्णायक नहीं रह गई है। इस बदलाव को केवल ‘पश्चिमी प्रभाव’ या ‘नैतिक गिरावट’ कहकर टाल देना ईमानदार विश्लेषण नहीं होगा। इसके पीछे गहरे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारण हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है।

आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, आत्मनिर्भर और समझ अव पहले जैसी निर्णायक नहीं रह गई है। इस बदलाव को केवल ‘पश्चिमी प्रभाव’ या ‘नैतिक गिरावट’ कहकर टाल देना ईमानदार विश्लेषण नहीं होगा। इसके पीछे गहरे सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कारण हैं, जिन्हें समझना आवश्यक है।

बाधक मानी जा रही है। भारतीय समाज में शादी एक समझौता नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन माना जाता है। लेकिन जब आज की पीढ़ी शादी को बोझ समझना शुरू कर दे और दूसरे साथी की जिम्मेदारी से घबराने लगे तो इन कल्पनाओं से जब वास्तविक जीवन टकराता है, तो निराशा पैदा होती है। छोटी-छोटी बातों पर संवाद के बजाय टकराव होने लगता है।

शादी केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि निरंतर संवाद, समझ और धैर्य की मांग करती है। आज के रिश्तों में ‘सुनने’ की जगह ‘कहने’ की प्रवृत्ति अधिक है। असहमति को स्वीकार करने और साथ मिलकर समाधान खोजने की संस्कृति कमजोर पड़ रही है। परिणामस्वरूप तनाव बढ़ता है और तलाक को आसान विकल्प मान लिया जाता है।

माता-पिता का अनुभव आज भी मूल्यवान है, पर युवा उसे हस्तक्षेप के रूप में देखने लगे हैं। वहीं माता-पिता भी बदलते समय और मानसिकता को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। इस

टकराव में विवाह जैसे फेसले और भी जटिल हो जाते हैं। इस स्थिति का समाधान न तो युवाओं को दोष देने में है और न ही परंपराओं को आँख मूँदकर थोपने में। जरूरत है ईमानदार संवाद, भावनात्मक शिक्षा और रिश्तों के प्रति यथार्थवादी दृष्टि की। विवाह को बोझ या मजबूरी नहीं, बल्कि साझेदारी और साझा जिम्मेदारी के रूप में समझना होगा। समाज, परिवार और युवा तीनों को यह स्वीकार करना होगा कि समय बदला है, पर रिश्तों की बुनियादी जरूरतें, सम्मान, समझ, धैर्य और संवाद अब भी उतनी ही जरूरी हैं। इन्हीं मूल्यों को नए संदर्भ में अपनाना ही विवाह संस्था को फिर से सार्थक और सफल बनाया जा सकता है।

अरुणोदय पत्रकारिता सम्मान व पुरस्कार समारोह 20 को, वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट होंगे सम्मानित

राजकुमार रैकवार, आलोक बैनर्जी, लाली कोष्टा, आशीष रैकवार, राजेन्द्र पांडे, दृष्टि जैन, शिव चौबे होंगे पुरस्कृत

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। अरुणशुक्ला पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारों के सम्मान व युवा पत्रकारों की हौसलाअफजाई के उद्देश्य से प्रतिवर्ष दिया जाता है। इस वर्ष चयन समिति ने पत्रकारों का चयन किया है। जिसमें वरिष्ठ पत्रकारिता सम्मान के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट को देने का निर्णय लिया है। श्री चैतन्य भट्ट लगभग चार दशकों से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में युवा पत्रकारों की हौसलाअफजाई के लिए माया स्मृति महिला पत्रकारिता पुरस्कार एक ऐसी महिला पत्रकार दृष्टि जैन को दिया जा रहा है। जो जबलपुर की निवासी है और नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस अखबार के संपादकीय विभाग में कार्यरत है। यशभारत कार्यालय में आयोजित चयन समिति बैठक में हिन्दी एक्सप्रेस के संपादक रविन्द्र बाजपेई, दैनिक भास्कर के डॉ पंकज शुक्ला, पत्रिका के शुभम सिंह बघेल, नई दुनिया के उज्जवल शुक्ला, यशलोक के सच्चिदानंद शेकटकर, प्रदेश टुडे के पवन पांडे, यशभारत के प्रवीण अग्रहरि

ने गगर के श्रेष्ठ पत्रकारों का चयन किया।

चयनित पत्रकारों के नाम इस प्रकार से हैं- श्री चैतन्य भट्ट- स्वतंत्र पत्रकार जबलपुर पत्रकारिता पुरस्कार, राजकुमार रैकवार (दैनिक भास्कर), आलोक बैनर्जी (नई दुनिया), लाली कोष्टा (पत्रिका), आशीष रैकवार (यशभारत कटनी), राजेन्द्र पांडे (प्रदेश टुडे)।

श्रीमती माया देवी श्रेष्ठ महिला पत्रकारिता पुरस्कार दृष्टि जैन (इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली)

इलेक्ट्रानिक (टीवी-9

शिव चौबे (मिडिया भारत वर्ष)

यशभारत के संस्थापक आशीष शुक्ला ने बताया कि पुरस्कार समारोह पं. अरुण शुक्ला के जन्मदिन एवं निर्वाण तिथि 20 फरवरी को अरुणोदय यशभारत कार्यालय परिसर शताब्दिपुरम उखरी में गरिमामय माहौल में आयोजित किया जाएगा। समारोह में नगर के चुनिंदा पत्रकारों व श्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शॉल श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और सम्मानतिथि से सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा इस मौके पर टेलीफोन वीडेक्टरी अरुणोदय 2026 का विमोचन भी अतिथियों के द्वारा किया जाएगा।

शब्दवीणा के नवगीत दिवस समारोह में साहित्यिक परिचर्चा व कवि सन्मेलन का आयोजन पत्रकार व कवि डॉ. एस. आनंद सिंह शब्दवीणा सहित्य गौरव सम्मान-2026 से हुए विभूषित

गया जी ।

राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था ‘शब्दवीणा’ की पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति के तत्त्वावधान में एवं प्रदेश अध्यक्ष राम नाथ बेखबर, उपाध्यक्ष हीरा लाल राम, संयोजक देवेश मिश्र, संगठन मंत्री डॉ शिव प्रकाश दास, कोषाध्यक्ष रामाकांत सिन्हा, साहित्य मंत्री ज्ञान प्रकाश पांडेय एवं प्रचार मंत्री डॉ संजीव दुबे के संयुक्त संयोजन में मॉर्रिंग ग्लोरी स्कूल, रिसड़ा में प्रथम नवगीत दिवस समारोह में साहित्यिक परिचर्चा एवं कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शब्दवीणा गीत एवं सरस्वती वंदना से हुआ। गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि डॉ. एस. आनंद सिंह को उनकी अनवरत साहित्य संधान के लिए ‘शब्दवीणा साहित्य गौरव सम्मान-2026’ से विभूषित किया गया। डॉ सिंह को मंचासीन कार्यक्रम अध्यक्ष ‘सदीनाम’ के संपादक जीतेन्द्र जितांशु, मुख्य अतिथि सेराज खान वातिश, विशिष्ट



अतिथि शकील गोंडवी एवं शंकर रावत सहित शब्दवीणा पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति के नेतृत्वकर्त्ताओं ने शॉल, विशेष स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। डॉ आनंद ने शब्दवीणा परिवार के प्रति प्राप्त अगाध स्नेह और सम्मान के लिए हार्दिक कृतज्ञता जताई। आमंत्रित सभी रचनाकारों को अंगवस्त्र प्रदान करके सम्मानित किया गया। मंचासीन वक्ताओं ने गीत और नवगीत पर उदाहरण सहित विचार रखे। नवगीत को काव्य विधा की नई और पुरानी धाराओं के संगम के रूप में बतलाया।

वक्ताओं ने कहा कि नवगीत हिंदी काव्य की एक आधुनिक विधा है जो ‘नई कविता’ के समानांतर विकसित हुई। इसमें आधुनिक संवेदनाएँ लोक-शैली में पिरोई जाती हैं, ताकि वे अधिक लोगों तक पहुँच सकें और उनका आनंद लिया जा सके। नवगीत लेखन का उद्देश्य लोगगीतों की परंपरा और आधुनिक भावबोध को मिलाकर सरल, गेय और समकालीन विषयों पर गीत लिखना रहा है। इसमें सामाजिक यथार्थ, लोक जीवन और मानवीय संवेदनाओं की प्रधानता होती है। इसमें एक मुखड़ा और कई छंदबद्ध अंते

होते हैं, जो लय, गति, और ताल से बंधे होते हैं, लेकिन पारंपरिक छंदों से मुक्त होते हैं। वक्ताओं ने नवगीत को नई कविता की जटिलता के विरोध में उत्पन्न काव्य विधा बतलाया, जिसमें आधुनिक जीवन के यथार्थ को सरल शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें मिट्टी से जुड़ाव का बोध होता है। सामाजिक असंतोष, वंचितों के प्रति करुणा, और मानवीय भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति होती है।

कार्यक्रम का संचालन राम नाथ बेखबर एवं डॉ शिव प्रकाश दास ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के सफल और सुनिर्वाचित आयोजन पर शब्दवीणा की संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. डॉ. रश्मि प्रियदर्शनी ने शब्दवीणा पश्चिम बंगाल प्रदेश इकाई को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं। कवि सम्मेलन में डॉ एस.आनंद, ज्ञान प्रकाश पाण्डेय, नन्दलाल रौशन, कमला पति पाण्डेय निडर, रमाकांत सिन्हा, राम नाथ बेखबर, डॉ शिव प्रकाश दास, संजीव दुबे, हीरालाल साव, देवेश मिश्रा, शंकर रावत आदि की उपस्थिति रही।

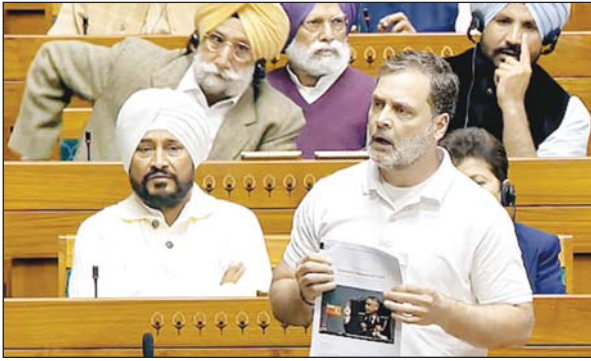


पीएम ने तबाव में किया अमेरिका से व्यापार समझौता-राहुल गांधी

नई दिल्ली।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विगत दिवस दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भयंकर दबाव में है, इसलिए उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री ने इस समझौते के माध्यम से किसानों और देश को बेच दिया है तथा इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी छवि का गुब्बारा कहीं फूट न जाए।

भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं जिसके तहत वाशिंगटन भारतीय उत्पादों पर शुल्क को कुल 50 प्रतिशत से कम करके 18 प्रतिशत करेगा। राहुल गांधी ने कहा, नरेन्द्र मोदी घबराए हुए हैं। जो व्यापार



समझौता चार महीने से रुका हुआ था, उसमें कुछ बदला नहीं और कल शाम उस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं जानता हूं और नरेन्द्र मोदी जानते है। उन्होंने दावा किया, मोदी जी पर भयंकर दबाव है। उनकी छवि का जो गुब्बारा है, जिसे हजारों करोड़ रुपए खर्च कर

बनाया गया था, वो फूट सकता है। असल में समस्या (पूर्व सेना प्रमुख एम एम) नरवणे जी का बयान नहीं है, ये तो साइड शो है। बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री कप्रोमाइन्ड हो चुके हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया, हिंदुस्तान के किसानों को यह समझना चाहिए कि इस समझौते में

आपकी मेहनत और खून-पसीने को नरेन्द्र मोदी जी ने बेच दिया है क्योंकि वह कप्रोमाइन्ड है। उन्होंने सिर्फ आपको नहीं, देश को बेच दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी छवि बनाई है, वही लोग उनकी छवि (का गुब्बारा) फोड़ने में लगे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया, प्रधानमंत्री पर दबाव का पीछे दो बातें हैं। पहला कारण एसटीन फाइल है। एप्सटीन फाइल में अभी बहुत सामग्री है, जिसे जारी नहीं किया गया है। इनमें जो है, उसे पूरा देश जानना चाहता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के दबाव में आने का दूसरा कारण अमेरिका में उद्योगपति गौतम अदाणी के खिलाफ दर्ज मामला है।

बजट में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए हुई कई महत्वपूर्ण घोषणाएं : राजपाल नियाणा

हरियाणा हांसी।

भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजपाल नियाणा ने विगत दिवस एक बयान जारी कर कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि को उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है जो पिछले साल से करीब 7 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने, छोटे-मझोले किसानों को विशेष ध्यान देने और ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने की बात कही है। केसीसी के तहत सॉफ्टिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को सस्ता और आसानी से ऋण मिलेगा, जिससे खेती-किसानी में निवेश बढ़ेगा। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने इस बजट में हाई वैल्यू फसलों पर खास जोर दिया

है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने और ज्यादा कमाई के लिए सरकार हाई वैल्यू उत्पादन जैसे काजू, अखरोट,नारियल, चंदन इत्यादि को सपोर्ट करेगी। पहाड़ी इलाकों में होने वाली खेती जैसे अखरोट, बादाम, खुमानी इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही ऐसी स्क्रीम लागू की जाएगी जिससे भूगोल स्थिति की वजह से होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत विस्तार की भी घोषणा की है। भारत विस्तार के जरिए किसानों को कई तरह के एक्सिस मिलेंगे। इसके जरिए किसानों के पास किसान कॉल सेंटर सर्विस का सीधा एक्सिस होगा। इसके साथ ही किसान एपीआई के जरिए मौसम की जानकारी ले पाएंगे।

उन्होंने बताया कि भारत विस्तार के जरिए किसानों को कई तरह की सुविधा जैसे कृषि से जुड़े प्रोसेस सिखना, कृषि से जुड़ी सरकारी स्क्रीम को ट्रैक करना इत्यादि आसान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बजट में ग्रामीण और पेरी अर्बन एरिया के पशुपालन सेक्टर पर खास फोकस रखा गया है। सरकार पशुपालन सेक्टर में होने वाली स्टार्टअप पर खास फोकस करेगी ताकि रोजगार में बढ़ोतरी हो।

परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : सीईओ जिला पंचायत

परीक्षा केंद्रों के केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों का प्रशिक्षण संपन्न

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। परीक्षाओं का सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने जिला प्रशासन द्वारा निरंतर तैयारियों का जा रही हैं। इसी क्रम में आज मॉडल स्कूल में परीक्षाओं के लिये निर्धारित किये गये सभी 100 परीक्षा केंद्रों में नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुये केन्द्राध्यक्षों एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों को सौंपें गये दायित्वों का पूरी निष्ठा और गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिये। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षा का संचालन पूर्णतः व्यवस्थित और निष्पक्ष हो, इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री गहलोत ने परीक्षा में नियुक्त सभी लोकसेवकों का भी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी, सजगता एवं ईमानदारी से करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने जानकारी दी कि बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से

प्रारंभ होकर 7 मार्च तक संचालित होंगी। जिले में कुल 100 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 96 नियमित एवं 04 निजी परीक्षा केंद्र शामिल हैं। इनमें से 04 परीक्षा केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जहाँ प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। कक्षा दसवीं में कुल 23 हजार 088 परीक्षार्थी एवं कक्षा बारहवीं में 18 हजार 640 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

जिला शिक्षा अधिकारी ने केन्द्राध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे परीक्षा के दौरान कलेक्टर प्रतिनिधि के साथ निर्धारित समय पर संबंधित थाने से प्रश्नपत्र प्राप्त कर परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित रूप से पहुँचाएं तथा सॉफ्टवेयर में आवश्यक प्रविष्टियाँ समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी सभी संबंधितों को देने, पर्यवेक्षकों की समय पर व्यवस्था कर अनुमोदन कराने, प्रश्नपत्र रखने वाले थानों में पूर्व से जाकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा गोपनीय सामग्री का वितरण समयबद्ध ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

सहायक संचालक एवं जिला परीक्षा प्रभारी आर के बधान द्वारा जिले के सभी 100 परीक्षा केंद्रों में नियुक्त केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्षों को नियुक्ति आदेश वितरित किये तथा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।

भारत-अमेरिका डील : भारत को आर्थिक, राजनीतिक गुलामी की ओर धकेलने वाला समझौता : आईपीएपी

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम तिवारी ने भारत सरकार द्वारा अमेरिका के साथ की जा रही तथाकथित भारत-अमेरिका डील पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समझौता देश के इतिहास की सबसे खतरनाक, आत्मघाती और राष्ट्रविरोधी डीलों में से एक है। यह डील भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र से अमेरिकी हितों की कठपुतली बनाने की दिशा में ले जा रही है। डॉ. तिवारी ने सवाल उठाया कि सरकार यह डील किसके दबाव में, किसके फायदे के लिए और देश के किस वर्ग के खिलाफ कर रही है-यह आज पूरे देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। डॉ. तिवारी ने कहा कि यह



डील भारतीय किसान की कपर तोड़ने दिा लिखित दस्तावेज है। भारतीय फसलों पर कड़े नियम और भारी टैरिफ, अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत में खुली छूट, एमएसपी और मंडी व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म करने की साजिश, किसान को कॉरपोरेट और विदेशी कंपनियों का गुलाम बनाने की तैयारी। यह डील लागू हुई तो किसान आत्मनिर्भर नहीं, आत्महत्या के लिए मजबूर होगा। भारत से निर्यात पर पारबंदियां और अमेरिका से आयात पर रियायतें-यह सीधी-सीधी आर्थिक लूट है। व्यापार संतुलन जानबूझकर भारत के खिलाफ रूपये को हर साल हजारों करोड़ रुपये का नुकसान। विदेशी मुद्रा भंडार पर सीधा हमला। रुपये की अंतरराष्ट्रीय साख कमजोर। यह नीति नहीं, देश को दिवालियेपन

की ओर धकेलने की साजिश है। सरकार एक ओर मेक इन इंडिया का नारा देती है और दूसरी ओर उसी की कन्न खुद खोद रही है। सस्ते अमेरिकी आयात से भारतीय उद्योग चौपट। एमएसएमई और छोटे कारखाने बंद होने की कगार पर। स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग खत्म। देश का उत्पादन विदेशी कंपनियों के हाथों गिरवी। यह मेक इन इंडिया नहीं, ब्रेक इन इंडिया है।

जब किसान बर्बाद होंगे और उद्योग बंद होंगे तो रोजगार कहाँ से आएगा युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। रोजगार सृजन की रफ्तार पूरी तरह ठप। पढ़ा-लिखा युवा हताश और मजबूर। यह डील युवाओं के भविष्य पर सीधा वार है। डॉ. तिवारी ने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति भी विदेशी दबाव में गिरवी रखी जा रही है। तेल-गैस के वैकल्पिक स्रोतों पर रोक। अमेरिका की मर्जी से ऊर्जा फैसले। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता समाप्त। भारत अब अपने हित में नहीं, विदेशी आदेश पर फैसले करेगा।

यह डील भारत की आजाद विदेश नीति का गला घोटने वाला समझौता है। बहुधुवीय नीति को कमजोर करना। अमेरिका के पक्ष में झुकाव। भारत का स्वतंत्र वैश्विक स्वरूप समाप्त। भारत को

हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिये एलाइंग स्काड गठित

जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग रोकने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने अनुभाग स्तर, जिला स्तर तथा विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दलों (फ्लाईंग स्काड) का गठन किया है। अनुभाग स्तर पर गठित फ्लाईंग स्काड की कमान संबंधित अनुभाग के एसडीएम को सौंपी गई है। वहीं, जिले में स्थित सभी परीक्षा केंद्रों के आकस्मिक निरीक्षण के लिये जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिला स्तरीय निरीक्षण दल का गठन किया है। इसके अलावा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दल (फ्लाईंग स्काड) भी गठित किये गये हैं। अनुभाग स्तर पर एसडीएम के नेतृत्व में गठित फ्लाईंग स्काड अपने अनुभाग में स्थित परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी।

खुनखुन न्याय पंचायत के ग्राम पीपा पुरवा में आयोजित हिंदू सम्मेलन



सत्य न्याय के लिए अड़ा हो वह हिंदू है। निजता से कर्तव्य बढ़ा हो वह हिंदू है। हिंदू घर में मात्र जन्म लेना पर्याप्त नहीं, हिंदू हित के लिए खड़ा हो वह हिंदू है।।
बिसबां/सीतापुर।

यह विचार राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला विमर्श प्रमुख साहित्य भूषण कमलेश मौर्य मृदु ने व्यक्त किये। वे यहां सकरन खंड के कम्हरिया खुनखुन न्याय पंचायत के ग्राम पीपा पुरवा में आयोजित हिंदू सम्मेलन में उपस्थित जनों की संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा वसुधैव कुटुम्बकम् व सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी संस्कृति है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना यही हमारा

पुलिस कर्मचारी ने हड़पी

महिला की जमीन

जबलपुर। थाना खमरिया क्षेत्र के सोनपुर वार्ड निवासी एक महिला ने एक पुलिस कर्मचारी और उसके भाई पर उसकी पेंतुक संपत्ति पर जब्तन कब्ज़ा करने, अश्लील गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। पीड़िता का आवेदन: कल्पना साहू ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को एक लिखित निवेदन दिया है, जिसमें उपरोक्त सभी आरोपों का विवरण दिया गया है और आरोपियों के नाम संदीप यादव व राजकुमार यादव के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। मामला गंभीर होने के कारण पीड़िता द्वारा पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है। यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस शिकायत पर कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।

फ्लाईओवर में दरार की खबर निराधार

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। लोक निर्माण विभाग संधाग क्रमांक-दो के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह ने दमोह नाका एक्सटेंशन फ्लाईओवर के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो को पूरी तरह भ्रामक और निराधार बताया है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के अनुसार, विगत दिवस सौरभ यादव (अध्यक्ष, मध्य भारत मोर्चा), दिलीप विश्वकर्मा, जानू शर्मा एवं शोभित राजपूत द्वारा इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल किया गया, जिसमें फ्लाईओवर में दरार होने का दावा किया गया था। कार्यपालन यंत्री ने स्पष्ट किया है कि वीडियो में दिखाई दे रहा हिस्सा कोई दरार नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से निर्मित एक ‘एक्सपांशन ज्वाईंट’ है, जो दो स्लैब के मध्य कंक्रीट के फैलाव और संकुचन को सुरक्षापूर्वक प्रबंधित करने के लिए दिया जाता है। कार्यपालन यंत्री ने कहा है कि इन व्यक्तियों ने लोक निर्माण के अभिरंयताओं से और कंटे्रक्टर मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रीवा से वास्तविक तथ्यों की जानकारी लिए बिना ही यह भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिससे आम जनता में भय की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने आम नागरिकों को सूचित किया है कि यह फ्लाईओवर आवागमन के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में सोशल मीडिया के माध्यम से तथ्यहीन और भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ने किया भ्रामक दावों का खंडन

कंडिका 3(3), 4(2), 9(घ) का उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 की सहपटित धारा 7 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के अनुसार घरेलू रसोई गैस के दुरुपयोग को रोकने कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम गोरखपुर अनुराग सिंह द्वारा अनुविभागवार जांच दलों का गठन किया गया था। इन जांच दलों में शामिल अधिकारियों द्वारा ग्राहक बनकर रसोई गैस वितरक एजेंसियों की जांच की गई थी। जाँच दल में शामिल अधिकारी खाली सिलेंडर लेकर रसोई गैस एजेंसी पहुँचे थे और भरे हुये सिलेंडर क्रय करने की मांग गैस एजेंसी के कर्मचारियों से की गई थी।

जाँच में दोषी पाए गए गैस वितरक एजेंसियों के कर्मचारियों द्वारा गैर पंजीकृत उपभोक्ता होने के बावजूद जांच अधिकारियों को निर्धारित दर 860 रुपये के स्थान पर एक हजार रुपये से 1हजार 400 रुपये लेकर प्रदान कर दिये गये। जांच दल के अधिकारियों द्वारा बकायदा इसके वीडियो बनाये गये और भुगतान भी यूपीआई के माध्यम से किया गया।

आचार्य भरत मुनि का नाट्य शास्त्र आज के युग में संजीवनी औषधि के समान है: उदय परांजपे

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। संपूर्ण विश्व की नाट्य विधाओं के पिता महाशास्त्रकार आचार्य भरत मुनि के जन्म जयंती के अवसर पर शासकीय मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में श्री मान उदय परांजपे जी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र शिक्षण मंडल, कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मार्गदर्शक डॉ स्मृति शुक्ला प्राचार्या मानकुंवर बाई महिला महाविद्यालय जबलपुर, विशिष्ट अतिथि श्रीमान प्रभात जी दुबे कार्यकारी अध्यक्ष संस्कार भारती जबलपुर, सारस्वत अतिथि डॉ अरुण विभाग अध्यक्ष चित्रकला एवं कार्यक्रम संयोजक डॉ नूपुर निखिल देशकर विभाग अध्यक्ष संगीत एवं भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ प्रभारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रचलन सरस्वती वंदना से हुआ। उसके पश्चात अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्रभात जी द्वारा संस्कार भारती का परिचय दिया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉ स्मृति शुक्ला जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में आचार्य भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र का सार प्रस्तुत करते हुए अभिनय और रस सिद्धांत पर प्रकाश डाला। सारस्वत अतिथि डॉ अरुण जी ने ‘चित्रकला में भरत मुनि का योगदान’ इस विषय पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम संयोजक डॉ नूपूर निखिल देशकर ने संगीत और भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न



आयामों में भरत मुनि की वैज्ञानिक दृष्टि पर अपना उद्बोधन दिया।

मुख्य अतिथि उदय परांजपे जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का आज के समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में जिन बिंदुओं को प्रस्तुत किया है आज वह सारे बिंदु मानवीय समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने कलाकार को समाज को मार्गदर्शन देने वाला कहा कार्यक्रम का संचालन संगीत विभाग की अध्यापक डॉ संगीता राय ने किया। आभार प्रदर्शन संगीत विभाग की अध्यापक डॉ उज्ज्वला अग्रचित ने किया। कु शबनम मेहरा, कु अंजली विश्वकर्मा, वपन पटेल, साक्षी प्रजापति, सखी जैन ने सरस्वती उदमा और स्वागत गीत की सामूहिक प्रस्तुतियां दी कार्यक्रम में चिकित्सक डॉ अनीता उदय परांजपे, श्री मान दिनेश बागरी (बघोजी)जी संस्कार भारती महानगर प्रचार प्रमुख आदि की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की।



3 घंटे में भोपाल तो साढ़े तीन घंटे में पूरा हो जाएगा जबलपुर से रायपुर का सफर

शहर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा

आगामी प्रोजेक्ट्स और केंद्रीय बजट पर की चर्चा

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा, जिसने विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार 9वाँ बार संसद में बजट प्रस्तुत कर रही हैं। यह अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हुआ है। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने केंद्रीय बजट 2026 विषय पर भाजपा संभागीय कार्यालय रानीताल में आयोजित पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर प्रदेश के लोक



निर्माण मंत्री राकेश सिंह, जिला अध्यक्ष रबेश सोनकर, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, नगर निगम अध्यक्ष रिकूज विज, रंजीत पटेल, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकान्त साहू, सह प्रभारी रवि शर्मा उपस्थित रहे।

जबलपुर होगा पूर्ण विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर

मंत्री श्री टम्टा ने कहा कि एनएचआई द्वारा 9278 किमी की, 47 सड़क

परियोजनाओं का कार्य हो रहा है। मप्र के साथ ही जबलपुर में भी तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है। जिले के चारों ओर 114 किमी लम्बी जबलपुर रिंग रोड (4-लेन) का निर्माण कार्य किया रहा है, जिसकी कुल लगत 3500 करोड़ रुपये है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य 5 पैकेजों में किया जा रहा है, जिसमे पैकेज-1 बरेला से मानेगांव तक का कार्य मार्च-2026 तक, पैकेज-2 मानेगांव से भोपाल राजमार्ग तक का कार्य जून-2026 तक, पैकेज-3 एवं 4 भोपाल राजमार्ग से अमझर तक जून 2026

तक एवं पैकेज-5 अमझर से बरेला तक अक्टूबर-2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार पूरी जबलपुर रिंग रोड कार्य अक्टूबर-2027 तक पूर्ण हो जायेगा। उन्होंने बताया जबलपुर जिले को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने का लिए विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत डीपीआर का कार्य किया जा रहा है, जिनमे दमोह-जबलपुर खण्ड मार्ग का 2 लेन + प्लेड शोल्डर / 4-लेन की तर्ज पर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु डीपीआर का कार्य प्रगतिरत है एवं परियोजना स्वीकृति हेतु लंबित है।

जल्द बनेगा स्पीड कॉरिडोर

तीन दिन का लक्ष्य... 100 प्रतिशत परिणाम

लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों को लेकर विभाग प्रमुखों को निगमायुक्त के निर्देश



जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने निगम के विभिन्न विभागों में लंबित सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना और हेल्पलाइन के प्रकरणों का 100 प्रतिशत निराकरण करना ही निगम का मुख्य लक्ष्य है। निगमायुक्त ने समय-सीमा का ध्यान रखने पर जोर देते हुए कहा कि 10 फरवरी तक जिन प्रकरणों पर संतोषजनक निराकरण की कार्यवाही नहीं की जाएगी, उनके संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निगमायुक्त ने इस बात पर जोर दिया कि आवेदनों पर त्वरित निराकरण के लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की आपसी समन्वय और टीम वर्क से ही समाधान की गति बढ़ेगी। कई बार एक शिकायत कई विभागों से जुड़ी होती है, ऐसे में आपसी संवाद से फाइनल को जल्दी क्लियर किया जा सकता है। निगमायुक्त ने विशेष रूप से लोककर्म, स्वास्थ्य, भवन, कॉलोनी सेल, जल, फायर, स्थाना, राज्य विभागों के प्रमुखों को लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बंद करने के निर्देश दिए।

500 करोड़ की लागत से सुधरेंगी बरगी बांध की क्षतिग्रस्त नहरें



जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। बरगी डैम की दाईं तट नहर विगत एक फरवरी को क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके चलते नहर का पानी पास से बह रहे नरई नाले में चला गया और खेतों में भर गया। इस दौरान बाढ़ जैसे हालात बन गए और फसलें जलमग्न हो गईं। जानकारी मिलते ही प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (एनवीडीए) के अधिकारी मौके पर पहुंचे। तत्काल डैम से आने वाला पानी बंद कराया गया और जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि नहर का करीब 27 मीटर हिस्सा खटो है। ऐसे समय नहर के क्षतिग्रस्त होने से पानी रिस रहा था। विभाग का दावा है कि क्षतिग्रस्त हिस्से की जल्द मरम्मत कर ली जाएगी। साथ ही किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। बता दें कि रबी सीजन में जब खेतों में गेहूं और अरहर की फसल खड़ी है। ऐसे समय नहर के क्षतिग्रस्त होने से किसानों की चिंता बढ़ गई। आशंका थी कि यदि समय पर पानी नहीं पहुंचा तो सैकड़ों एकड़ में लगी फसल सूख सकती है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का कहना है कि हर हाल में 15 से 20 फरवरी तक नहर को फिर से चालू कर दिया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत माइनर नहरों से भी पानी दिया जा रहा है। मरम्मत कार्य में तेजी लाने के लिए 100 से अधिक मजदूर, जेसीबी मशीन और एक्सकेवेटर लगाए गए हैं।

बैंक अधिकारी के साथ मिलकर ठेकेदार ने भुना ली 82 लाख रुपये की एफडी

कार्य न होने पर नर्मदा विकास विभाग ने किया था ब्लैकलिस्टेड

पनागर थाना क्षेत्र का मामला एफआईआर दर्ज

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।



नर्मदा विकास विभाग के तहत कुण्ड वितरण नहर एवं इसके वितरण नहर प्रणाली का निर्माण कार्य की निविदा लेने वाले ठेकेदार और बैंक अधिकारी ने मिलकर विभाग को 82 लाख रूपए की चपत लगा दी है। दोनों ने सांठगांठ करके बैंक में रखी एफडीआर चोरी-छिपे धुना ली। अब इस मामले की जानकारी मिलते एफआईआर की गई है। इस मामले में पनागर पुलिस ने बताया कि नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 02 के कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार भालाधरे ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमे लेख है कि नर्मदा विकास अंतर्गत कुण्ड वितरण नहर एवं

इसके वितरण नहर प्रणाली का निर्माण कार्य निविदा स्वीकृति 21 अक्टूबर 2004 के माध्यम से ठेकेदार मेसर्स कर्नाटका लेण्ड आर्मी बैंगलोर को दिया गया था, परंतु ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य निर्धारित समयवधि में पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभाग द्वारा विभाग एवं ठेकेदार के मध्य हुये अनुबंध को निरस्त किया गया। अनुबंध निरस्त किये जाने के विरोध में ठेकेदार द्वारा माध्यम अभिकरण में अपील की गई। माध्यस्थम अभिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय दिनांक 7 सितंबर 2022 के आदेशानुसार ठेकेदार की जमा दो नग बैंक गारंटी 43 लाख

75 हजार रूपए एवं 43 लाख 75 हजार के रूप में यूनियन बैंक सिविक सेंटर, मढ़ाताल से बैंक ड्राफ्ट बनाकर राजसात की गई। तत्पश्चात् ठेकेदार की जमा मूल एफडीआर दो नग के नगदीकरण हेतु शाखा प्रबंधक, यूनियन बैंक मढ़ाताल को पत्र लिखा गया। यूनियन बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि तकनीकी खराबी एवं पुरानी एफडीआर होने के कारण एकाउंट नंबर नहीं मिल रहा है जिसके कारण एफडीआर का नगदीकरण नहीं हो पा रहा है। एफडीआर का नगदीकरण किये जाने हेतु पुनः शाखा प्रबंधक

यूनियन बैंक मढ़ाताल सिविक सेंटर को पत्र लिखा गया। शाखा प्रबंधक द्वारा अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि उक्त एफडीआर का नगदीकरण वर्ष 2015 में हो चुका हैं। ठेकेदार के खाते में एफडीआर की राशियां अंतरित कर दी गई है।

शासन को पहुंचाई हानि

शाखा यूनियन बैंक द्वारा इस तरह अवैधानिक रूप से नियम विरुद्ध कृत्य किये जाने पर इस कार्यालय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया कि मूल एफडीआर इस कार्यालय में जमा है फिर किस आधार पर एफडीआर की राशि ठेकेदार के खाते में अंतरित कर दी गई। पुलिस ने समस्त अभिलेखों सहित मंगये गये एवं जांच उपरांत पाया गया कि शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक मढ़ाताल सिविक सेंटर द्वारा कूटरचित ढंग से ठेकेदार को एफडीआर राशि का भुगतान करते हुये शासन को बहुत बड़ी हानि पहुंचाई गई है।

परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से विद्यार्थियों का तनाव कम होता है : विधायक अशोक रोहाणी

जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम शासकीय मॉडल स्कूल में आयोजित

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी पहल 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम का नवां संस्करण आज पूरे देश में एक साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण देशभर के सभी विद्यालयों में किया गया, जिसे विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक देखा।

कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी, समय प्रबंधन, तनावमुक्त रहकर अध्ययन करने तथा आत्मविश्वास बनाए रखने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री घनश्याम सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 9वां संस्करण दिनांक 19 जनवरी 2026 से 23 जनवरी 2026 तक दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों ने सहभागिता की। यह प्रथम अवसर था जब प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पर विद्यार्थियों से संवाद किया।

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के छात्र आनुष तिवारी, कक्षा 11वीं, पं. लज्जा शंकर



झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का चयन इस गौरवशाली अवसर के लिए हुआ। आयुष तिवारी अपने संरक्षक शिक्षिका डॉ. भारती मालपानी के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने विद्यार्थियों के साथ नाश्ते पर संवाद किया एवं उन्हें असमी गमछा पहनाकर सम्मानित किया।

जबलपुर जिले का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय मॉडल स्कूल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र विधायक माननीय अशोक रोहाणी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के उपाध्यक्ष माननीय श्रीनिवास राव जी तथा भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी उपस्थित

रहे। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ कार्यक्रम का ऑनलाइन प्रसारण देखा एवं इसकी सराहना की।

कार्यक्रम के पश्चात् विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक श्री अशोक रोहाणी जी ने कहा कि, परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का भय और तनाव दूर करते हैं, जिससे वे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं।

विशिष्ट अतिथि श्रीनिवास राव जी ने कार्यक्रम को रोचक एवं अत्यंत उपयोगी बताया, वहीं श्री अखिलेश जैन जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे इस वर्ष उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी से संवाद करने वाले छात्र आनुष तिवारी का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में एडीपीसी श्री गौतम बर्बे, डीपीसी श्री योगेश शर्मा, प्राचार्य श्रीमती उपमा गुप्ता, विधि प्रभारी श्री कृष्णकान्त शर्मा, सहित शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि जिले के समस्त विद्यालयों में 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रही।



एकजुटता के साथ सरकार तक पहुंचाएंगे अपनी समस्याएं

स्वतंत्रता संग्राम

सेनानी के वंशजों

की बैठक सम्पन्न

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)।

रविवार को जबलपुर शहर जिला ग्रामीण एवं शहरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के वंशजों उत्तराधिकारियों परिजनों की गांधी भवन टाउन हॉल प्रांगण में वंशज उत्तराधिकारी वरिष्ठ सदस्य एड प्रकाश गोलछा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक के प्रारंभ में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की

प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।

सदस्यता अभियान की शुरुआत

बैठक में बताया गया कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार के प्रदेश के अध्यक्ष अजय नारायण सितलानी के निर्देशन पर जबलपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मठ एवं जुझारू उत्तराधिकारियों वंशजों को संगठन एवं प्रकोष्ठ में सदस्यता अभियान के तहत जोड़ा जावेगा और जिला ग्रामीण अध्यक्ष एवं शहरी नगर अध्यक्ष दोनों अध्यक्षों

की कार्यकारिणी में सेनानी परिवार के उत्तराधिकारी वंशजों को महत्वपूर्ण पदों का मनोनयन भोपाल प्रदेश मुख्यालय से शीघ्र ही सूची जारी की जायेगी। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों को संगठन के विस्तार के बाद जबलपु संगठन एक जुटता के साथ इन मुद्दों को लेकर समस्याओं को लेकर सरकार को स्मरण करायेगी। इस अवसर पर उत्तराधिकारी वंशज मनोज नामदेव, राजेन्द्र रज्जू सराफ, ओम प्रकाश जायसवाल, ओम शर्मा, गुरु प्रसाद नीखरा, प्रीति चौधरी, मदन मोहन राय, निर्मल चंद जैन, अनिल उसरेटे आदि उपस्थित रहे।



पुराने फाउंडेशन पर स्थापित किया गया अधिक क्षमता का कैपेसिटर बैंक

जबलपुर (खबर प्लेटफार्म)। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) के इंजीनियरों ने तकनीकी दक्षता एवं उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। इंजीनियर्स ने एक 132 केवी सबस्टेशन में तकनीकी नवाचार का परिचय देते हुए पुराने कैपेसिटर बैंक के फाउंडेशन पर ही अधिक क्षमता का नया कैपेसिटर बैंक सफलतापूर्वक स्थापित कर ऊर्जीकृत किया है। इससे सबस्टेशन से जुड़े क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण बिजली मानक वोल्टेज लेवल पर उपलब्ध हो रही है।

वोल्टेज प्रोफाइल हो रहा था प्रभावित

आगर स्थित 132 के वी सब स्टेशन में इंडक्टिव लोड बढ़ने के कारण पूर्व में स्थापित 5 एमवीएआर क्षमता का कैपेसिटर बैंक अपर्याप्त हो गया था, जिससे वोल्टेज प्रोफाइल प्रभावित हो रही थी। सीमित स्थान के कारण नए फाउंडेशन का निर्माण संभव नहीं था। इस चुनौती का समाधान करते हुए एमपी ट्रांसको के सहायक अभियंता योगेश राठौर ने कार्यपालन अभियंता शेखर फटाले के मार्गदर्शन मे पुराने फाउंडेशन का ही उपयोग कर आवश्यक तकनीकी संशोधन किए और उसी फाउंडेशन पर 12 एमवीएआर क्षमता का नया कैपेसिटर बैंक स्थापित किया। इससे समय, लागत और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता से बचाव हुआ।